(पाश की कविताएं)

हमारे समयों में

यह सबकुछ हमारे ही समयों में होना था
कि समय ने रुक जाना था थके हुए युद्ध की तरह
और कच्ची दीवारों पर लटकते कैलेंडरों ने
प्रधानमंत्री की फोटो बनकर रह जाना था

धूप से तिड़की हुई दीवारों के परखचों
और धुएं को तरसते चूल्हों ने
हमारे ही समयों का गीत बनना था

गरीब की बेटी की तरह बढ़ रहा
इस देश के सम्मान का पौधा
हमारे रोज घटते कद के कंधों पर ही उगना था
शानदार एटमी तजर्बे की मिट्टी
हमारी आत्मा में फैले हुए रेगिस्तान से उड़नी थी

मेरे–आपके दिलों की सड़क के मस्तक पर जमना था
रोटी मांगने आए अध्यापकों के मस्तक की नसों का लहू
दशहरे के मैदान में
गुम हुई सीता नहीं, बस तेल का टिन मांगते हुए
रावण हमारे ही बूढ़ों को बनना था
अपमान वक्त का हमारे ही समयों में होना था
हिटलर की बेटी ने जिंदगी के खेतों की मां बनकर
खुद हिटलर का 'डरौना'
हमारे ही मस्तकों में गड़ाना था।
यह शर्मनाक हादसा हमारे ही साथ होना था
कि दुनिया के सबसे पवित्र शब्दों ने
बन जाना था सिंहासन की खड़ाऊं–
मार्क्स का सिंह–जैसा सिर
दिल्ली की भूल–भूलैयों में मिमियाता फिरता
हमें ही देखना था
मेरे यारो, यह कुफ्र हमारे ही समयों में होना था

बहुत दफा, पक्के पुलों पर
लड़ाइयां हुईं
लेकिन जुल्म की शमशीर के
घूंघट न मुड़ सकें
मेरे यारो, अपने अकेले जीने की खाहिश कोई पीतल का छल्ला है
हर पल जो घिस रहा
न इसने यार की निशानी बनना है
न मुश्किल वक्त में रकम बनना है

मेरे यारो, हमारे वक्त का एहसास
बस इतना ही न रह जाए
कि हम धीमे–धीमे मरने को ही
जीना समझ बैठे थे
कि समय हमारी घड़ियों से नहीं
हड्डियों के खुरने से मापे गए

यह गौरव हमारे ही समयों को मिलेगा
कि उन्होंने नफरत निथार ली
गुजरते गंदलाए समुद्रों से
कि उन्होंने बींध दिया पिलपिली मुहब्बत का तेंदुआ
और वह तैरकर जा पहुंचे
हुस्न की दहलीजों पर

यह गौरव हमारे ही समयों का होगा
यह गौरव हमारे ही समयों का होना है।

पेज 1 का शेष भाग

एम्बुलेंस फ़ोन नं. 102 सेवा नहीं विज्ञापन बाजी

इस तरह के उल्लेखनीय केसों में गांव मिर्जापुर की उर्मिला 15 फ़रवरी की रात में जब अस्पताल पहुंची तो स्टाफ़ की गुंडागर्दी व प्रताड़ना के चलते उसे बाथरूम में ही बच्चा जनना पड़ा था। इसी तरह 19 नवम्बर 2012 को जब सौंध गांव की अंजू को पलवल के सरकारी अस्पताल द्वारा गंभीर हालत में रात के दो बजे बादशाह खान रैफ़र किया गया तो उसने यहां एक बच्चे को जन्म तो दिया लेकिन उसे 4-5 घंटे बाद ही अस्पताल से बाहर खदेड़ दिया गया, बिना उसकी शारीरिक स्थिति का ध्यान रखे।

उक्त बबीता वाले मामले की जांच करने पर इस संवाददाता को पता चला कि उस रात अस्पताल में लेडी डॉक्टर रजनी की ड्यूटी थी। लेकिन पी एम ओ मेहता द्वारा चलाई जा रही परम्परा के अनुसार रात की ड्यूटी कोई डाक्टर खासकर लेडी डाक्टर नहीं करतीं। केवल रजिस्टर में उनकी हाजरी भर दी जाती है। जब पी एम ओ की मिलीभगत से डाक्टर ड्यूटी से नदारद रहेंगे तो मातहत स्टाफ़ भला क्यों काम करेगा? वह तो अपने ऊपर वालों को देख कर ही तो काम करेगा। रही बात एम्बुलेंस वाले फ़ोन नं. 102 की तो उसके लिये कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं पी एम ओ कहता है कि वह तो डॉक्टर एम एम शर्मा के तहत है और डा. शर्मा कहते हैं कि उनका इससे क्या ताल्लुक। दरअसल ताल्लुक तो केवल उस जनता का है जो इन 'सेवाओं' को भुगत रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं में संसाधनों की कमी तो है ही परन्तु जो हैं भी उनका जिस तरह दुरूपयोग हो रहा है, जिस तरह से बर्बादी की जा रही है, वह कोढ में खाज के समान है। बी के अस्पताल की खंडरह हो चुकी पुरानी इमारत की जगह नई ईमारत बना दी गयी। करोड़ों रुपया खर्च हो गया लेकिन उसके डिजायन व निर्माण में की गयी लापरवाहियां तथा भ्रष्टाचार के चलते इस इमारत का उतना लाभ नहीं हो पा रहा जितना पैसा खर्च किया गया है। पेस्ट एवं चूहों आदि से इमारत को मुक्त रखने के लिये सालाना 30 000 रुपया का ठेका दिया जाता है इसके बावजूद आप्रेशन थियेटर के डक्ट में चूहे बेखौफ़ कबड्डी खेलते देखे जा सकते हैं।

इन चूहों की मुख्य खुराक ओ टी में गिरने वाला मानवीय खून आदि होता है। दरअसल इसमें 30 000 रुपया लेने वाले ठेकेदार की ज़्यादा गलती नहीं है जब पी एम ओ उससे आधे पैसे एडवांस में ले लेगा तो वह पेस्ट कंट्रोल तो फ़िर ऐसा ही करेगा।

डाक्टर जो ड्यूटी से नदारद रहतें हैं वे कोई मुफ्त में नहीं रहते, वे इसके लिये बाकायदा पी एम ओ को नकद पैसा देते हैं। केजुअल्टी में आने वाले पुलिस केसों से होने वाली मोटी लूट वसूलने के लिये डॉक्टर मेहता केवल उन्हीं डॉक्टरों को नियुक्त करते हैं जो उन्हें लूट में से बराबर हिस्सा देते रहें।

अपनी तमाम नालायकियों व खुली लूट के बावजूद डॉक्टर मेहता यहां बतौर पी एम ओ कोई मुफ़्त में नहीं जमे बैठे हैं। इसके लिये वे बाकायदा उन तमाम नेताओं व अफ़सरों की पूरी सेवा करते हैं जो उन्हें यहां से उखाड़ फ़ेंकने में सक्षम हैं।

पुलिस की रिश्वतखोरी का सड़क पर धमाल

इसलिये किसी ने इनसे बचना हो तो बच लो ये तो टकराने को तैयार फ़िरते हैं। कृषि कार्यों के लिये बने ये ट्रैक्टर केवल खेतों में चलने के लिये ही पंजीकृत एवं अधिकृत होते हैं, इसीलिये इनसे कोई पंजीकरण शुल्क भी नहीं लिया जाता। वैसे कानून में प्रावधान है कि जिस ट्रैक्टर से कृषि कार्यों की अपेक्षा सड़कों पर माल ढोने का व्यवसाय करना हो तो उसके लिये शुल्क अदा करके परमिट लिया जा सकता है। इस तरह का परमिट लेने के लिये वाहन को सड़क पर चलाने के लिये हर तरह से फ़िट कर के पास करवाना अनिवार्य होता है। इन सब कामों पर खर्चा लगता है। इसे बचाने के लिये सीधा सरल व सस्ता उपाय है पुलिस को नियमित रिश्वत देना।

करीब 2 वर्ष पूर्व 'मज़दूर मोर्चा' द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार शहर में चलने वाले 1200 ट्रैक्टर ट्राले ट्रैफ़िक पुलिस को एक हज़ार मासिक देते थे। इनके अलावा जो ट्रैक्टर चलते हैं वे जगह-जगह बने पुलिस नाकों पर बाकायदा 'इन्ट्री' देते हैं जो 50 रुपया से 100 रुपया तक हो सकती है। जाहिर है ये अवैध वाहन पुलिस की रिश्वत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिये बेशक कितनी ही दुर्घटनायें क्यों न हो जायें पुलिस इनको बंद नहीं कर सकती । वैसे शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन इन से कोई न कोई दुर्घटना न होती हो फ़िर भी इनका बदस्तूर बेखौफ़ चलना स्वत: सिद्ध करता है कि पुलिस इन्हें बन्द करके अपनी कमाई छोड़ने वाली नहीं है।

पेज 5 का शेष भाग

जापान में अपराध स्वीकार करते हैं बेगुनाह लोग

जापान में अपराध के मामलों में सज़ा सुनाए जाने की दर 99 फीसदी है और जिसमें ज़्यादातर कबूलनामें पर आधारित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध स्वीकार करने के लिये तैयार हो तो अदालत उसे दोषी मान कर सज़ा दे देती है।

जापान में पुलिस के पास जांच के सीमित अधिकार हैं और वहां जांच से अधिक अपराधी के इकबालिया बयान को महत्त्व दिया जाता है। इसलिये पुलिस किसी बेगुनाह पर गुनाह कबूलने का दबाव बनाती है, ताकि वह अपनी कर्मठता साबित कर सके। हालत यह है कि साइबर क्राइम के नाम पर पुलिस द्वारा किये जाने वाले इस अपराध का शिकार कोई भी बेगुनाह हेा सकता है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता हो।

जापान जैसे विकसित देश में किस तरह इकबालिया बयान लिये जाते हैं ये उसकी एक छोटी सी तस्वीर भर हैं। हमारे देश में ये बयान किस तरह दर्ज किये जाते हैं यह सभी को पता ही है। इस काम के लिये हमारे यहां पुलिस थर्ड डिग्री और न जाने कितने तरह के अमानवीय तरीके अपनाती है। इतना ही नहीं, यहां फर्जी एनकाउन्टर आये दिन होने वाली पुलिस कार्रवाई बन गया है, जिस पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता। हिरासत में मौत, बिना वारन्ट गिरफ़्तारी और कई-कई दिनों तक उत्पीड़न करना काफी प्रचलित है। आज भी भारी तादाद में बेगुनाह लोग अपनी जिंदगी जेलों में गुजार रहे हैं। आखिर ये कैसा समाज है जो निर्दोष लोगों से जबरन इकबालिया बयान लेकर उन्हें सलाखों के पीछे डाल देता है। क्या ऐसे समाजों को लोकतंत्र कहना लोकतंत्र का मजाक नहीं?

-देश-विदेश

राज्यपाल वांचू ने पाया इनाम वेस्टलैंड सौदे का

ऐसे में सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली विशिष्ट चालबाज़ी अपनाई गयी। सौदे के बीच में वांछित हेलीकॉप्टर के स्पेसिफ़िकेशन (मापदंड) इस तरह बदल दिये गये ताकि केवल वेस्टलैंड ही उन पर खरे उतरें। उस समय वेस्टलैंड ही तीन इन्जन का हेलिकाप्टर बनाते थे और उनकी ऊंचाई अन्य हेलीकॉप्टरों से ज़्यादा होती थी। लिहाजा सुरक्षा और सुविधा के नाम पर ये दोनों मापदंड सरकारी निविदा में शामिल किये गये। जाहिर है एक मात्र प्रतिस्पर्धी को ही सौदा मिला।

पर सुरक्षा एवं सुविधा के तर्कों को लाये कौन? सारी दुनिया में बड़े से बड़े वी आई पी भी दो इन्जन एवं कम ऊंचाई वाले हेलिकॉप्टरों में सुरक्षित घूम रहे थे। यहां तक कि भारतीय पी एम एवं राष्ट्रपति भी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिये एस पी जी के तत्कालीन डायरेक्टर भरत वीर वांचू की 'सेवायें' ली गयीं। फ़ाइल इस बहाने से एस पी जी को भेजी गयी कि इन हेलिकॉप्टरों को पी एम की सेवा में भी लगना है और क्योंकि एस पी जी पी एम की सुरक्षा करती है, लिहाजा उनकी राय, लेना भी आवश्यक है। वांचू ने कहे अनुसार मापदंड बदलने की सिफ़ारिश की और सौदा फ़लीभूत करने में यह सिफ़ारिश काम आई । यहां यह जान लेना भी आवश्यक है कि एस पी जी सोनिया गांधी परिवार की बपौती वाला संगठन है।

श्री मति इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन पी एम राजीव गांधी के मार्गदर्शन में बने इस संगठन पर सोनिया परिवार का दबदबा पूरी तरह कायम रहा है। भरत वीर वांचू का एस पी जी से नाता प्रारंभ से ही रहा। वह एक सुरक्षा अधिकारी कम और गांधी परिवार का पालतू सेवक ज़्यादा रहा। उसे इसका इनाम भी मिला जब तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी कर उसे एस पी जी के डायरेक्टर पद पर बैठा दिया गया। यह आई पी एस अधिकारी 5 वर्ष डायरेक्टर एस पी जी रह कर अक्टूबर 2012 में सेवा से निवृत हुआ। गांधी परिवार को दी गयी 'सेवाओं' के एवज में इसे अब गोवा का राज्यपाल बनाया गया है।

वेस्लैंड फ़ाइल पर अनुकूल टिप्पणी लिखवाने के लिये वांचू को मशक्त भी करनी पड़ी थी। एस पी जी में कार्यरत गुजरात काडर के एक आई जी ने मामले की नजाकत को देखते हुए एस पी जी छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। उनके जाने के बाद आसाम काडर के एक आइ जी से फ़ाइल पर वांछित टिप्पणी हासिल की गयी।

इस घोटाले में यदि एनथोनी का रक्षा मन्त्रालय और भारत सरकार की सी बी आई वास्तव में सक्रिय होना चाहते हैं तो उन्हें हेलीकॉप्टर कम्पनी द्वारा राजनीतिज्ञों, वायुसेना अफ़सरों एवं बिचौलियों को दी गयी रकम के चैनलों की खोज खबर जुटानी होगी जो आज की तकनीकी के चलते कठिन काम नहीं है। केवल इटली सरकार पर निर्भरता दिखाने और वायुसेनाधिकारियों से पूछताछ का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा।

-त्रिनेत्र

मज़दूर मोर्चा

नियमित पढ़ने हेतु पाठकगण अपने हॉकर से संपर्क करें। जो हॉकर, आपके घरों में दैनिक अखबार डालते हैं, आपके आदेश पर मज़दूर मोर्चा भी डालेंगे।

कोई दिक्कत हो तो दीक्षित न्यूज़ एजेंसी से 9811159238 पर संपर्क करें।

'मज़दूर मोर्चा' प्रिंटफोर्ट, नेहरू ग्राउंड पर भी उपलब्ध है।